

IASbaba's Daily Prelims Test [Day 50]

TOPIC: Polity - Non-constitutional Bodies

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना कि देश में 'मानव अधिकार के प्रहरी' के पास पूर्णकालिक सदस्य के अलावा पदेन सदस्य हैं।

निम्नलिखित में से कौन पदेन सदस्य हैं?

1. अल्पसंख्यकों के लिए आयोग के अध्यक्ष ।
2. अनुसूचित जाति के लिए आयोग के अध्यक्ष ।
3. अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग के अध्यक्ष ।
4. महिलाओं के लिए आयोग के अध्यक्ष ।
5. बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग के अध्यक्ष ।

सही उत्तर चुनिए ।

1. केवल 2, 3.
2. केवल 2, 3, 4 .
3. केवल 1, 4, 5.
4. केवल 1, 2, 3, 4.

Answer: 4

2.राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में वाक्यो पर विचार करें।

1. मानव अधिकारों के संरक्षण के अधिकार अधिनियम, 1993 के तहत हर राज्य पर एक राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन करने का एक दायित्व है ।
2. यह केवल राज्य सूची में वर्णित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं।
3. मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में आयोग केवल घटना के एक वर्ष के भीतर में इसमें जाँच कर सकता है।

सही उत्तर चुनिए ।

1. केवल 1 .
2. केवल 2 .
3. दोनों 1 और 2
4. इनमे से कोई भी नहीं

Answer: 2

वक्तव्य 1 गलत है-मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 अनिवार्य रूप से एक राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करने की सरकार से मांग नहीं करता है।

वक्तव्य 2 गलत है - एक राज्य मानवाधिकार आयोग केवल राज्य सूची (सूची- II) और संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची- III) में उल्लेख किये गए विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं। किसी भी तरह के मामले में पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य वैधानिक आयोग द्वारा जांच की जा रही है । हालांकि, राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है।

वक्तव्य 3 सही है -आयोग की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, जिस में मानव अधिकारों के उल्लंघन का गठन कानून के लिए प्रतिबद्ध किये जाने का आरोप है। दूसरे शब्दों में, यह घटना के एक वर्ष के भीतर मामले पर गौर कर सकते हैं।

3. निम्नलिखित वाक्यों पर गौर करें:

1. वेतन, भत्ते और मुख्य सूचना आयुक्त की अन्य सेवाएं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए समान हैं।
2. वेतन, भत्ते और मुख्य सतर्कता आयुक्त की अन्य सेवाएं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए समान हैं।

सही उत्तर चुनिए |

- 1) केवल 1
- 2) केवल 2
- 3) दोनों
- 4) इनमें से कोई भी नहीं।

Answer: 3

4.राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में वाक्यों पर विचार करें।

1. संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही आयोग के सदस्यों को राज्य मंत्रिमंडल से सिफारिश के बाद एक राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है |

2. सदस्यों को हटाया जाना विशेष राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं , बल्कि यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है।

सही उत्तर चुनिए ।

1. केवल 1.
2. केवल 2 .
3. दोनों.
4. इनमे से कोई भी नहीं।

Answer: 4

आयोग के एक राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और दस से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं होते हैं । वे अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री से मिलकर एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, विधान सभा में विपक्ष के नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा नामित किये जाते हैं। वे व्यापक ज्ञान और अनुभव कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन के साथ सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के व्यक्तित्व होने चाहिए ।

राज्यपाल सदस्यों को हटा सकते हैं , भारत के राष्ट्रपति को नहीं ।

5. भारत के संविधान के अनुसार, निम्नलिखित वाक्यों में से कौनसा सही है?

1. सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए ।
2. सभी के बिल, नियमों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उपनियमों आदि की आधिकारिक ग्रंथ अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

सही उत्तर चुनिए ।

1. केवल 1 .
2. केवल 2 .
3. दोनों.
4. इनमे से कोई भी नहीं।

Answer: 2

सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्यवाहियां केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाना चाहिए।

6.अखिल भारतीय सेवा के बारे में वाक्यो पर विचार करें।

1. अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने के लिए कोई भी संसद के अनन्य क्षेत्राधिकार है और दोनों लोकसभा के साथ-साथ राज्य सभा में इस के लिए सम्मान के साथ बराबर शक्तियों को साझा करते हैं ।
2. इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (दंड लगाए जाने की) केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा दोनों में ली जा सकती है।
3. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केन्द्र सरकार का होता है।

सही उत्तर चुनिए ।

1. केवल 1, 2 .
2. केवल 2, 3 .
3. केवल 3 .
4. उपरोक्त सभी।

Answer: 3

किसी भी अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने के लिए, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है जो लोकसभा के पास नहीं है।

केवल केन्द्र सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती हैं, जिसमें भव्य दंड शामिल है।

7. राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष
2. सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
3. यह केन्द्र सरकार को ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों को भी सिफारिशें करता है।

सही उत्तर चुनिए |

1. 1 और 3
2. 1 और 2
3. 2 और 3
4. 1, 2 और 3

Answer: 4

8. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित सदस्य जो शामिल नहीं है?

1. रक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारियों को।
2. असैनिक कर्मचारियों को छोड़कर रक्षा बल के सदस्य।

3. सुप्रीम कोर्ट के सेवक और अधिकारी।
4. संसद के सचिवालय कर्मचारी।

सही उत्तर चुनिए |

1. केवल 2 .
2. केवल 2, 3 .
3. केवल 2, 3, 4.
4. केवल 1, 3, 4.

Answer: 3

कैबिनेट भर्ती और लोक सेवकों की सभी सेवा के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार रखता है | रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों के तहत अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवा, सिविल पदों पर इसका क्षेत्राधिकार केंद्र फैला हुआ है | हालांकि, रक्षा बलों के अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट और संसद के सचिवालय स्टाफ के सेवकों के सदस्यों में इसका क्षेत्राधिकार नहीं है |

9. पिछड़ा वर्ग समुदायों के संरक्षण और विकास के लिए भारत के संविधान के अंतर्गत क्या प्रावधान है ?

1. Article 15.
2. Article 16.
3. Article 46.
4. Article 338.

सही उत्तर चुनिए |

1. केवल 1, 2 .
2. केवल 1, 2, 3 .

3. केवल 1, 3, 4 .
4. उपरोक्त सभी।

Answer: 4

अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रावधान में दो महत्वपूर्ण शब्द 'भेदभाव' और 'केवल' हैं। शब्द 'भेदभाव' का तात्पर्य एक प्रतिकूल अंतर बनाने के लिए या 'दूसरों से भेद करना' है। 'केवल' शब्द का प्रयोग अन्य आधार पर भेदभाव निषिद्ध नहीं है, यह बताता है। राज्य के नागरिकों की या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने के लिए अनुमति दी है। उदाहरण के लिए, जनता के शिक्षण संस्थानों में सीटें या शुल्क रियायतें का आरक्षण।

अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान की जाएगी।

कोई भी नागरिक भेदभाव या केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म या निवास स्थान के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता है। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण के लिए या किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पद प्रदान कर सकते हैं, जो पर्याप्त रूप से राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है।

राज्य समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक और आर्थिक हितों और अन्य कमजोर वर्गों को बढ़ावा देने के लिए और सामाजिक अन्याय और शोषण (अनुच्छेद 46) से बचाने के लिए कानून बना सकते हैं।

अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है। यह अनुसूचित जाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग, एंग्लो भारतीयों के संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है।

10.भारत के संविधान के तहत एंग्लो भारतीयों के लिए प्रावधानों के बारे में वाक्यों पर विचार करें।

1. राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करना होता है ।
2. किसी राज्य का राज्यपाल, राज्य विधान सभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं यदि समुदाय को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है ।

सही उत्तर चुनिए ।

1. केवल1 .
2. केवल2 .
3. इनमे से कोई भी नहीं।

Answer: 2

लोकसभा के दो सदस्यों को मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से कोई दायित्व नहीं है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय पर्याप्त रूप से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा है।